

एक लायसेंस और दो परियोजनाओं के लिए डीजल सप्लाई कर रही कलिंगा

नियम विरुद्ध की जा रही डीजल की सप्लाई और खपत से सरकार को लग रहा करोड़ों का चूना, जांच की मांग

सिंगरौली। एनसीएल में ओबी हटाने के लिए आउटसोर्सिंग कम्पनी कलिंगा को दो परियोजना में टेंडर मिला है। जिनमें एक म.प्र. के झिंगुरदह में और दूसरी उ.प्र. के खड़िया शक्तिनगर में संचालित है। जहां ओबी के कार्य के लिए टेंडर लेने वाली कलिंगा कंपनी नियमों को दरकिनार कर शासन को करोड़ों का चूना लगाने पर तुली हुई है।

सूत्र बताते हैं कि पेट्रोलियम और बिस्फोटक सुरक्षा संगठन पीईएसओ के तहत खदान क्षेत्रों में आवश्यकताओं के मद्देनजर पेट्रोलियम पदार्थों के संग्रहण की अनुमति दी जाती है। जहां यह अनुमति म.प्र. के झिंगुरदह में कार्य कर रही कलिंगा कंपनी के पास है। लेकिन एनसीएल खड़िया में ओबी का कार्य कर रही कलिंगा ने अभी यह परमीशन नहीं ली है और वह झिंगुरदह के लायसेंस पर ही डीजल की आपूर्ति और खपत कर रही है। प्रश्न यह उठता है कि आईओसी से डीजल लेकर टैंकर एनसीएल झिंगुरदह परियोजना के लिए चलता है तो वह खड़िया परियोजना में कैसे पहुँचता है,



अर्थात स्थानीय पेट्रोल पंपों से सप्लाई होना है, जो कि निर्धारित लायसेंस कीमत से 5 रुपये ज्यादा है। ऐसे में 40 हजार लीटर प्रतिदिन की खपत के आधार पर 2 लाख रुपये दिन का राजस्व नुकसान उ.प्र. शासन को हो रहा है। इस मामले में अगर जांच कराई जाये तो कलिंगा कंपनी के द्वारा की जा रही लापरवाही का खुलासा होगा। जहां डीजल के नाम पर अब तक करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति शासन को उठाना पड़ा है।

उच्चस्तरीय जांच पर दोनों कंपनियों पर कार्रवाई

सूत्रों का कहना है कि पीईएसओ के नियमों के तहत जहां पेट्रोलियम पदार्थों की उपयोगिता निर्धारित है, उसका उपयोग उसी स्थान पर होना चाहिए। लेकिन एक लायसेंस पर दो स्थानों जो कि अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं के लिए होना नियमों की अवहेलना है और ऐसे हालातों में दोनों स्थानों पर कार्यरत कंपनियों के लिए लायसेंस निरस्तीकरण और कार्रवाई का प्रावधान है। कहा जा रहा है कि ऐसे हालातों में शासन-प्रशासन हो रहे राजस्व नुकसान पर कलिंगा खड़िया पर क्या कार्रवाई करता है। यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

वहहाल इस पूरे मामले में चल रहे घालमेल से शासन को लाखों का चूना लग रहा है। जब इस सम्बन्ध में एनसीएल के जन संपर्क अधिकारी रामविजय सिंह से बात की गयी तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर कलिंगा के अधिकारी ही बता सकते हैं।

मुगलसराय से कटता है चालान

बताया जाता है कि वर्तमान में एक लायसेंस के आधार पर दो कंपनियों को की जा रही आपूर्ति में डीजल के लिए चालान मुगलसराय डिपो से जारी होता है। जो कि एनसीएल कलिंगा झिंगुरदह म.प्र. के नाम काटा जाता है। जानकारों का कहना है कि इस लायसेंस का दुरुपयोग कर झिंगुरदह कंपनी कलिंगा खड़िया को डीजल प्रदान कर रही है। इस मामले में डीजल की खपत भी कास हो रही है। लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारी आंखे बंद किए हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि झिंगुरदह परियोजना के लिए लगभग 70 हजार लीटर डीजल उपलब्ध कराये जाने को लिमिट है और दो गाड़ी अर्थात 40 हजार लीटर डीजल की आपूर्ति खड़िया स्थित प्रोजेक्ट पर खर्च हो रहा है। जो जांच का विषय है। बताया जाता है कि खड़िया में डीजल की खपत के लिए परमीशन जिला प्रशासन सोनभद्र से लेना होती है, लेकिन अभी तक कलिंगा कंपनी ने कोई पत्र सोनभद्र प्रशासन को नहीं भेजा है।

लंबित प्रकरणों का समय सीमा के अंदर निराकरण करे : कलेक्टर

जिला एवं विकास में भी ई-ऑफिस के माध्यम से नस्तियों को किया जाये संधारण



सिंगरौली। सीएम हेल्पलाईन समाधान बिंदु, सीएम आवास, सीएम कार्यालय सहित आयोगों से प्राप्त पत्रों का समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही जिला स्तर के साथ-साथ विकास खण्ड स्तर के कार्यालयों में भी ई-ऑफिस के माध्यम से नस्तियों का संधारण किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त आशय का निर्देश समय सीमा के बैठक के दौरान कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा विभागीय अधिकारियों को दिया गया। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाईन में लंबित शिकायतों के साथ-साथ समाधान बिंदु तथा

सीएम आवास, सीएम कार्यालय सहित विभिन्न आयोगों के प्राप्त होने वाले पत्रों के निराकरण के प्रगति की जानकारी लेने के पश्चात निर्देश दिए कि अभी भी शिकायतों का निराकरण शत-प्रतिशत नहीं किया गया है। इसे गंभीरता से लिया जाये तथा आगामी बैठक में निराकरण की प्रगति की जानकारी भी दिया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने छात्रावासों के साथ-साथ विद्यालय भवनों, आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी लेने के पश्चात निर्देश दिए कि जर्जर भवनों में छात्रों को नहीं बैठाये, इसके लिए उचित प्रबंध करे। साथ ही छात्रावासों में रहने

वाले छात्राओं की नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराये। साथ ही यह भी कहा कि महिला बाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि धात्री एवं गर्भवती महिलाओं का समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराये तथा समय समय पर पोषण आहार भी उपलब्ध कराये। बैठक के दौरान जिपं सीईओ गजेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर पीके सेन गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, एसडीएम सुजन बर्मा, ननि आयुक्त डीके शर्मा, डिप्टी कलेक्टर माइकेल तिर्की, देवेन्द्र द्विवेदी, नंदन तिवारी सहित जिलाधिकारी मौजूद रहे।

हर-हर महादेव के उद्घोष से गुंजे शिवालय, भक्तो ने टेका माथा

प्रथम सोमवार को मंदिरों में उमड़ी भक्तो की भीड़

सिंगरौली। श्रावण मास के प्रथम सोमवार के उपलक्ष्य में शिवधाम मंदिर बैदुन में मंदिर के महाप्रबंधक ज्योतिषविद् पं. डॉ. एनपी मिश्र के सानिध्य में अनेकानेक भक्तजनों द्वारा भूतभावना भोलेनाथ महाभृत्जंय भगवान की पूजा अर्चना एवं कई भक्तों द्वारा सामूहिक रूप से रुद्रभिषेक कर पुण्य लाभ प्राप्त किया गया। शाम महिला भक्तजनों द्वारा भजन कीर्तन किया गया। ज्योतिषविद् पं. डॉ. एनपी मिश्र के अनुसार श्रावण मास में गगन से झरते अमृत तुल्य



अमूल्य रत्न हैं, जिन पर श्रद्धा का दीप प्रज्वलित कर व्यक्ति अपने जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति का पथ प्रशस्त करता है। ज्योतिषविद् पं. डॉ. एनपी मिश्र महाप्रबंधक शिवधाम मंदिर बैदुन ने बताया पौराणिक आख्यानों में वर्णित है कि जब समुंद्र मंथन में महाविष प्रकट हुआ, तब समस्त संसार को उससे उत्पन्न विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया और उसका प्रभाव उनके कंठ में स्थिर हो गया।

दिशा समिति के अध्यक्ष होंगे सांसद

सिंगरौली। भारत सरकार द्वारा जिला स्तरीय समिति जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिसके तहत समिति की अध्यक्षता सीधी-सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्र करेंगे तथा कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला समिति के सदस्य सचिव होंगे। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत समिति में सदस्य के रूप में सुरेन्द्र प्रताप सिंह वैश्य, लालजी शाह, मोतीलाल प्रजापति व मधु झा, विद्यासागर तिवारी, सुनीता साकेत, मेघनाथ वैश्य, बाबूराम जायसवाल, दुलमती सिंह का सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

भास्कर मिश्रा के गिरफ्तारी के बाद सीएसपी सवालों के लपेटे में

चौतरफा शुरु है विरोध, स्कूल एवं कोचिंग के बयान को लेकर आमजन उठा रहे सवाल

सिंगरौली। कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद सीएसपी विन्ध्यनगर निशाने पर आ गये हैं। आम से लेकर खास तक इस कार्रवाई की चारो तरफ भर्त्सना हो रही है। वही अब दबी जुबान में सत्ता पक्ष के लोग भी उक्त कार्रवाई को अनुचित ठहराते हुये सीएसपी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा ने पिछले 20 दिनों से सड़क हारसे को लेकर चिंता जाहिर करते हुये समस्या के समाधान के लिए परसौना में 13 जुलाई को चक्काजाम आंदोलन करने का ऐलान किया था और कहा था कि कोल वाहनों को ही रोका जाएगा। यात्रिवसों के साथ कोई रोक-टोक नहीं होगा। बीते दिन कल सुबह

कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा जैसे ही परसौना तिराहा पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, तभी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ली। इनकी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया में जहां तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। साथ ही विपक्षी दल के कई नेता व आम खास भी भास्कर मिश्रा के समर्थन में लोग सड़क पर उतर आये और सीएसपी पीएस परस्ते का विरोध शुरू हो गया। इधर न्यायालय के द्वारा भास्क र मिश्रा को जेल भेज दिया गया। हालांकि आज दिन सोमवार को भास्कर मिश्रा एवं उनके आधा दर्जन साथियों को जमानत मिल गई। लेकिन भास्कर मिश्रा के गिरफ्तारी को लेकर चारो तरफ विरोध के स्वर गूंजने लगे। आलम यह है कि अब यही चर्चा है कि विन्ध्यनगर सीएसपी

ने जल्दबाजी में या आत्मविश्वास के चलते कदम उठाया या फिर विपक्षी दलों को बैठे-बैठाये प्रदेश सरकार को घेरने का एक अच्छा मौका दे दिया और बीते दिन कल से ही लगातार विपक्षी दल कोतवाली पुलिस एवं सीएसपी तथा प्रदेश सरकार पर सोशल मीडिया के माध्यम से तरह-तरह के बातों को जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों के ना समझी एवं नादानी का परिणाम है कि प्रदेश सरकार की ऊर्जाधानी में चारो तरफ किरकिरी हो रही है। कहा जा रहा है कि चक्काजाम सिंगरौली में आम बात है। भास्कर मिश्रा एवं उनके समर्थक परसौना में चक्काजाम कर रहे थे तो इसमें जनहिताथ से तात्कालिक था। भास्कर मिश्रा का व्यक्तिगत कुछ

भी नहीं शामिल था। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने भास्कर मिश्रा एवं उनके समर्थकों को सरकार को घेरने के लिए अवसर दे दिया। साथ ही सीएसपी का स्कूलो वाला बयान भी लोगों के गले से बात नहीं उतर रही है। प्रबुद्ध लोग यही कह रहे हैं कि सीएसपी के बयान का भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार सण्डे को कौन सी विद्यालय व कोचिंग सेंटर संचालित रहती हैं। सोशल मीडिया में लोगबाग सीएसपी से उन कोचिंग सेंटर एवं विद्यालयों का नाम भी पूछ रहे हैं। फिलहाल भास्कर मिश्रा पर पुलिसिया कार्रवाई से भाजपा सरकार की किरकिरी हो रही है। साथ ही भाजपा के कुछ नेता भी मान रहे हैं कि सीएसपी के लिए नादानी सरकार के लिए भारी पड़ रहा है।

ईव्हीएम मशीनो का प्रथम रेण्डमाईजेशन आयोजित

सिंगरौली। जनपद पंचायत क्षेत्रांतर्गत एवं चितरंगी जनपद पंचायत अंतर्गत अकस्मिक रूप से रिक्त हुये सरपंच पद के उप निर्वाचन के लिए लगने वाली ईव्हीएम मशीनो का प्रथम रेण्डमाईजेशन कलेक्टर चन्द्र शेखर शुक्ला एवं अभ्यार्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों के उपस्थित में ईव्हीएम मशीनों के प्रथम रेण्डमाईजेशन का कार्य पूर्ण किया गया।

चितरंगी क्षेत्र की बिजली व्यवस्था चरमराई, उपभोक्ता परेशान

पिछले चार दिनों से घंटो रहती है बिजली गुल, पावर का ट्रांसफार्मर खराब



और हर आधे-एक घंटे में बिजली गुल हो रही है। इस समस्या से

उपभोक्ता काफी परेशान हैं। बीती रात चितरंगी शहर अंधेरे में डूबा रहा। वही बिजली सप्लाई कर्तृआ सब स्टेशन से अस्थाई रूप से सप्लाई की जा रही है, लेकिन वह नाकाफी है और लोग वोल्टेज की समस्या निर्मित है। करीब एक सैकड़ गांव इन दिनों बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। चर्चा है कि हैवी ट्रांसफार्मर सतना में भी नहीं है। हालांकि कार्यपालन अभियंता

एमपीईबी ग्रामीण के द्वारा नये ट्रांसफार्मरों के लिए प्रस्ताव भेजा है।

इनका कहना

ट्रांसफार्मर खराब है। नये ट्रांसफार्मर के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। वैकल्पिक व्यवस्था कर्तृआ सब स्टेशन से की गई है।

ओपी द्विवेदी

कार्यपालन अभियंता, एमपीईबी, बैदुन ग्रामीण

दित्यांग जनों के लिए शिविर का आयोजन आज

सिंगरौली

दिव्यांग जनों के लिए विशेष शिविरो का आयोजन 15 जुलाई से तीनों जनपद क्षेत्रांतर्गत आयोजित किए जायेंगे। जिसमें जाँच उपरांत दिव्यांगों के लिए कृतिम अंग एवं वृद्धजन के लिए उपकरण चिन्हंकन किया जायेगा। जिसके तहत जनपद पंचायत

देवसर क्षेत्रांतर्गत के नगर परिषद सरई के गांधी बाई एवं ग्राम पंचायत बागाडीह में शिविर का आयोजन होगा। वही चितरंगी क्षेत्रांतर्गत के ग्राम पंचायत गोपला में बैदुन जनपद पंचायत क्षेत्रांतर्गत के ग्राम पंचायत जमगाड़ी में शिविर का आयोजन होगा। शिविर का आयोजन प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक किया जायेगा।

ऊर्जाचल विस्थापित कल्याण समिति की साप्ताहिक योजना बैठक आयोजित

एनटीपीसी तृतीय चरण विस्तार योजना के साथ पुनर्वास कॉलोनियों का हो विकास



सिंगरौली। एनटीपीसी तृतीय चरण विस्तार परियोजना के अंतर्गत परियोजना में 800 मेगावाट की दो सुपर क्रिटिकल यूनिट का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में परियोजना के विस्थापित परिवारों में पुनर्वास कॉलोनियों के विकास मूलभूत सुविधाओं की

विस्थापित परिवार को रोजगार एवं शिक्षा चिकित्सा प्रदूषण मुक्ति पर योजना के साथ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है। विस्थापित बेरोजगारों को विस्तार योजना में रोजगार में समायोजन करने की आवश्यकता है। साप्ताहिक योजना बैठक में प्रमुख रूप से रामकरण चौबे, जंग बहादुर चौबे, शैलेंद्र चौबे, अशोक पाण्डेय, बृज बिहारी यादव, नंदलाल भारती, चिंतामणि जायसवाल, योगेंद्र सिंह, अमरकेश पाण्डेय, पंकज शुक्ला, गणेश मिश्रा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष हेमंत मिश्र द्वारा किया गया।

कुशल का टोटा, अकुशल श्रमिकों के लिए दबाव

सिंगरौली। कोयला क्षेत्र में हजारों-करोड़ का कार्य कर रही निजी कंपनियां कुशल श्रमिकों की कमी से जूझ रही हैं। दूसरी तरफ नेता अकुशल कामगारों को नियोजित करने का दबाव बना रहे हैं। इससे कंपनियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।

यूपी-एमपी के सीमावर्ती क्षेत्र में एनसीएल की 10 खदानों से कोयला उत्पादन होता है। कोयला निकासी के निमित्त पहाड़ों का मलबा ओवर बर्डन हटाने के लिए आउटसोर्स की मदद ली जा रही है। इसके पीछे मकसद मांग मुताबिक कोयला उत्पादन करना है। आउटसोर्सिंग कंपनियों में कई हजार श्रमिक नियोजित हैं। रोजगार के

लिहाज से कंपनियां बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी मददगार बनी हैं, लेकिन टकराव कुशल व अकुशल श्रमिकों को लेकर है। खनन कार्य पूरी तरह मशीनीकृत है। ऐसे में डंपर, डोजर, ग्रेडर सहित अन्य इक्वूपमेंट के प्रचालन के लिए कुशल कामगारों की जरूरत बढ़ गई है। कंपनियों के नुमाइंदों का कहना है कि कुशल कर्मियों के अनुपात में ही अकुशल श्रमिकों को नियोजित किया जा सकता है। मशीनीकृत युग में अकुशल की यह संख्या बेहद कम है। इस मसले को समझने के बजाए स्थानीय लोग नेताओं के जरिए अकुशल श्रमिकों के नियोजन

के लिए दबाव बनाते हैं और इसका खामियाजा कंपनियों को आंदोलन प्रदर्शन, फर्जी मुकदमों के रूप में झेलना पड़ता है। बेवजह के इन विवादों से लक्ष्य निर्धारित कार्य प्रभावित हो रहा है। हाल के दिनों में एनसीएल बीना व खड़िया कोयला क्षेत्रों में आंदोलनों के चलते कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके ठीक विपरित नेता कोल प्रबंधन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट प्रभावित परिवारों व विस्थापित सदस्यों के रोजगार के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। इसी के चलते टकराव की स्थिति पैदा हो रही है।

इनका कहना

एनसीएल और कंपनी दोनों के द्वारा युवाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग कराना चाहिए। इससे विस्थापित और प्रभावित परिवारों को रोजगार मिल सकता है।

राजन भारती, महाप्रबंधक विस्थापित युवा कल्याण समिति

सन 1960 से विस्थापन का दंस झेल रहे विस्थापितों के लिए आज तक सरकार

और कोल प्रबंधन ने कोई ठोस नीति नहीं बना पाई। एनआईटी में भी स्पष्टता का आभाव है। सरकार और कोल इंडिया को चाहिए कि अकुशल, अर्धकुशल में 80 फीसदी विस्थापितों की भागीदारी सुनिश्चित करे।

अरविंद दुबे
विस्थापित नेता

इनका कहना

एनसीएल कोशल विकास व भारत सरकार की संकल्प योजना के तहत स्थानीय युवाओं को खनन क्षेत्र की जरूरत मुताबिक प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है। आवश्यकता अनुसार इसका दायरा बढ़ाया जाएगा।

राम विजय सिंह

प्रवक्ता, एनसीएल

केन्द्रीय जेल रीवा में बरसात के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए चर्म रोग से संबंधित बीमारियों के बचाव एवं निदान हेतु श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के चर्मरोग विभाग के 10 सदस्यीय चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम द्वारा विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।



इंजीनियरिंग कॉलेज के सुदृढीकरण से विन्ध्य क्षेत्र के समग्र विकास को मिलेगी गति : उप मुख्यमंत्री

रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की दीर्घकालिक विकास योजना पर विस्तृत चर्चा कर दिए निर्देश

रीवा। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज विन्ध्य क्षेत्र का एक प्रमुख तकनीकी शिक्षण संस्थान है, जिसकी सुदृढ़ता न केवल क्षेत्रीय तकनीकी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएगी, बल्कि विन्ध्य क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति देगी। उन्होंने कहा कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के तकनीकी सशक्तिकरण से आने वाले समय में विन्ध्य अंचल उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित होगा। यह संस्थान स्थानीय युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने के साथ-साथ प्रदेश की तकनीकी क्षमताओं को भी विस्तार देगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की दीर्घकालिक विकास योजना पर



विस्तृत चर्चा की। बैठक में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री विवेक पोरवाल एवं रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आर.पी. तिवारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित

करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि शिक्षण गुणवत्ता के लिए योग्य शिक्षकों की भर्ती अहम है। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्तमान पाठ्यक्रम के विधिवत संचालन के लिए स्वीकृत पदों की पूर्ति के साथ नवीन पाठ्यक्रम के लिए विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण

शिक्षा का आधार उत्कृष्ट शिक्षण संकाय होता है। सभी विभागों में योग्य, अनुभवी एवं नवाचारोन्मुख फैकल्टी की शीघ्र भर्ती की जाए ताकि छात्रों को वैश्विक स्तर की तकनीकी शिक्षा मिल सके। इसके लिए रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज को विभाग आवश्यक सहयोग प्रदान करे। समय की मांग अनुसार नवीन कोर्स का संचालन करें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित योजनाओं को शीघ्र अनुमोदन की प्रक्रिया में लाया जाए। प्राचार्य डॉ. तिवारी ने कॉलेज की 5 वर्षीय एवं 20 वर्षीय सुदृढीकरण योजना प्रस्तुत की। उन्होंने 88.30 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत, अधोसंरचना विकास और अन्य सुविधाओं के विस्तार का रोडमैप

प्रस्तुत किया। प्रस्तावित योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एवं फायर टेक एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग जैसे समसामयिक विषयों में 5 नवीन यूजी प्रोग्राम तथा साइबर सिनियोरिटी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, डिजिटल कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन डिजाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एडवांस प्रोडक्शन सिस्टम सहित 9 पीजी प्रोग्राम प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव शामिल है। साथ ही 17.53 करोड़ रुपये की लागत से सेंट्रल लाइब्रेरी, 12.33 करोड़ रुपए लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और 1.45 करोड़ रुपए लागत से इन्व्यूबेशन सेंटर के निर्माण कार्य विकास योजना में शामिल है।

प्रशिक्षण देने के लिए अतिथि व्याख्याताओं से 25 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

रीवा। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रीवा में प्रशिक्षण देने के लिए अतिथि व्याख्याताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में संस्था के प्राचार्य ने बताया कि प्रशिक्षण केन्द्र में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों को राज्य सिविल सेवा परीक्षा, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी तथा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं से आगामी 25 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

निर्धारित अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति के साथ कार्यालयीन समय में कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र केन्द्र के ईमेल पीईटीसीआईडब्ल्यूए एट द रेट ज़ीमेल डॉट कॉम अथवा रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा जा सकता है। प्राचार्य ने बताया कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अध्यापन किए जाने विषय एवं संबंधित प्रतियोगी परीक्षा का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। आवेदक संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो अथवा किसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान जहाँ से प्रशिक्षणार्थियों का चयन प्रतियोगी

परीक्षाओं में होता रहा हो, में संकाय का सदस्य रहा हो। अतिथि व्याख्याताओं के चयन के लिए गठित समिति द्वारा व्याख्याताओं का पैनल तैयार किया जाएगा। अतिथि व्याख्याताओं को समय-समय पर आयोजित होने प्रशिक्षण में उन्हें व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया जाएगा तथा शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में प्रतिकालखण्ड के लिए 800 रुपए मानदेय निर्धारित है। एक कालखण्ड कम से कम 90 मिनट का होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्य उम्मीदवारों का चयन राज्य शासन के निर्देशानुसार केन्द्र में गठित समिति द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

क्षेत्र में भ्रमण कर निर्माण कार्यों की सतत मानीटरिंग करें

जलमग्न होने वाले पुल और रपटों में तत्काल बैरियर लगाएं : कमिश्नर



ओर से आवागमन बंद कराएं। अधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे करके इनमें सुधार का कार्य शुरू करें। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि निर्माण कार्य में यदि भू अर्जन की आवश्यकता है तो कार्य स्वीकृत होते ही भू अर्जन की कार्यवाही शुरू कर दें। निर्माण एजेंसी को वर्क आर्डर जारी करने के साथ ही कार्य के लिए आवश्यक भूमि भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। भू अर्जन के संबंध में कलेक्टर कार्यालय में आयोजित टीएल बैठक में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं। नागौद, परसमनिया, मैहर मार्ग निर्माण के लिए वन विभाग से समन्वय बनाकर कार्य पूरा कराएं। सीतापुर से बदवार मांग में शेष बचे चार किलोमीटर का कार्य एक माह में पूरा करें। रीवा-

आवश्यक भूमि भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। भू अर्जन के संबंध में कलेक्टर कार्यालय में आयोजित टीएल बैठक में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं। नागौद, परसमनिया, मैहर मार्ग निर्माण के लिए वन विभाग से समन्वय बनाकर कार्य पूरा कराएं। सीतापुर से बदवार मांग में शेष बचे चार किलोमीटर का कार्य एक माह में पूरा करें। रीवा-

प्रयागराज मार्ग में सोहागी घाट में सड़क में सुधार का कार्य तत्काल शुरू कराएं। सभी फोरलेन सड़कों में डिवाइडर में पौधे रोपित कराएं। रोपित पौधों की सुरक्षा के भी उचित प्रबंध करें। विभागीय मद से 243 सड़कों का संभाग के विभिन्न जिलों में निर्माण किया जा रहा है। इनमें से अभी केवल 39 सड़कों का कार्य पूरा हुआ है। शेष 165 प्रगतिरत सड़कों का कार्य समय पर पूरा कराएं।

कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग पीआईयू की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम राज्ञ स्कूल रामपुर बघेलान, उंचेहरा तथा मझगावां में समस्त औपचारिकताएं पूरी करके निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराएं। निर्माण कार्यों में जमीन के संबंध में किसी भी तरह

की कठिनाई होने पर कलेक्टर को अवगत कराएं। मैहर जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 39 शासकीय आवास मंजूर हुए हैं। इनका निर्माण कार्य तत्काल शुरू करें। छात्रावास भवन के लिए भी उपयुक्त स्थल तय करके निर्माण कार्य शुरू कराएं। मैहर में ही सर्किट हाउस में अतिरिक्त कक्ष और रामगढ़ के शासकीय स्कूल भवन के निर्माण की बाधाएं दूर करके उनका कार्य शुरू करें। बैठक में रीवा बायपास के उन्नयन, सीधी-सिंगरौली हाईवे के निर्माण, मऊगंज में शासकीय आवास निर्माण सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य अभियंता आरके वर्मा ने सड़कों तथा अन्य निर्माण कार्यों की जिलेवार जानकारी दी।

केन्द्रीय जेल में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

रीवा। केन्द्रीय जेल में बरसात के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए चर्म रोग से संबंधित बीमारियों के बचाव एवं निदान हेतु श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के चर्मरोग विभाग के 10 सदस्यीय चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम द्वारा विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर 134 पुरुष बंदी, 20 महिला बंदी सहित कुल 154 बंदिशों को चर्मरोग से संबंधित उपचार प्रदान किया गया।

पुल और रपटों में लगाए गए बैरियर

रीवा। जिले में 11 जुलाई को लगातार भारी वर्षा के कारण कई पुल, रपटे और पुलिया जलमग्न हो गए। इनमें किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग नितिन पटेल ने बताया कि रीवा-गड्डी रोड में 15वें किलोमीटर में धोबी नाला में अधिक पानी आने पर



आवागमन को रोकने के लिए दोनों ओर बैरियर लगाया गया है।

है। गोविंदगढ़ से टीकर होकर लक्ष्मणपुर जाने वाली सड़क में बिल्छिया नदी के रपटे पर छिरहटा गांव में भी दोनों ओर ड्रप गेट बनाए गए हैं। जिले की अन्य सड़कों में भी इसी तरह छोटे पुलों और रपटों में जल भराव होने पर बैरियर लगाकर वाहनों को रोकने की व्यवस्था की जा रही है।

कमिश्नर आज करेंगे टीएल पत्रों की समीक्षा

रीवा। कमिश्नर बीएस जामोद 15 जुलाई को टीएल पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। बैठक कमिश्नर कार्यालय सभागार में सुबह 11 बजे आरंभ होगी। बैठक में ई ऑफिस व्यवस्था, पेंशन प्रकरणों के निराकरण तथा विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।

परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए आवेदन 30 जुलाई तक

रीवा। मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बीमा, नर्सिंग एवं म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल में चयन के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों से आगामी 30 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इस संबंध में प्राचार्य परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र ने बताया कि आवेदन पत्र स्वयं अथवा रजिस्टर्ड

डाक से कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति अथवा जनजातीय का सदस्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तय की गयी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो। प्रशिक्षण के

लिए चयनित होने पर प्रशिक्षार्थी को 500 रुपये सुरक्षानिधि जमा करके अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र शा. ज्ञानोदय विद्यालय अनुसूचित जाति कल्याण विभाग परिसर से प्राप्त की जा सकती है। जानकारी प्राप्त करने के लिए फोन नंबर 07662-299221 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

न्यायाधीशगणों द्वारा किया गया बालकों को जागरूक

रीवा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में तथा जिला न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह राठौड़ व डॉ. श्रीमती अंजली पारे तथा न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री समीर कुमार मिश्र के नेतृत्व में आदर्श उ.मा.वि. में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि श्री सुधीर सिंह राठौड़ ने अपने उद्बोधन में बालकों को सकारात्मक जीवन शैली अपनाने, उनके मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों



का पालन करने और किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जानकारी दी। डॉ. श्रीमती अंजली पारे ने बच्चों को गुडटच एवं बैडटच के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं श्री समीर कुमार

मिश्र ने कहा कि अपने मन को भटकाव से बचना है और ऐसा कार्य करना है जिससे हमारा परिवार हमारा समाज गौरवान्वित हो। उन्होंने बालकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी

दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे बताया। लीगल एड. डिफेंस के असिस्टेंट श्री अनीश कुमार पाण्डेय ने विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। स्वागत उद्बोधन अधिका सुनील अग्रवाल द्वारा दिया गया। संचालन श्रीमती श्रुति पाण्डेय तथा आभार विद्यालय के डायरेक्टर सुभाषु पयासी द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य डॉ. मनोज पाण्डेय एवं सचिन गुप्ता सहित समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राये उपस्थित रहे।

अवरूढ़ ईक्वीएम का निस्तारण 16 जुलाई को

रीवा। कपिध्वज सिंह बनाम नागेन्द्र सिंह के प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय अनुमति के अनुपालन में अवरूढ़ ईक्वीएम का निस्तारण शासकीय इंजीनियरिंग कालेज परिसर स्थित ईक्वीएम वेयर हाउस में 16 जुलाई को शाम 5 बजे किया जायेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निस्तारण के दौरान आवेदक, अनावेदक सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/प्रतिनिधियों से उपस्थिति की अपेक्षा की है।

स्ट्रांग रूम खोला जायेगा

रीवा। कपिध्वज सिंह विरूद्ध नागेन्द्र सिंह के प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के विधानसभा क्षेत्र 75 गुढ़ की निर्वाचन याचिका में अवरूढ़ ईक्वीएम के निस्तारण हेतु विधानसभा क्षेत्र 75 गुढ़ का स्ट्रांग रूम खोलने की अनुमति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई है।